GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

S.No.PC-V/42 R.B.E. No.32/98
No.PC-V/97/I/7/17 New Delhi, dated 09.02.1998

The GMs/CAO(R)/OSDs.
All Indian Railways &
Production Units etc.
(as per mailing list)

Sub : Grant of Overtime Allowance to Railway employees consequent upon revision of pay scales and allowances

The Fifth Central Pay Commission have not found adequate justification for payment of Overtime Allowance in the Central Government Offices, and have recommended its discontinuance. They have, instead, recommended that compensatory leave may be given to the staff deployed on weekly off days.

2. The matter has been carefully considered by the Railway Board and it has been decided that payment of Overtime Allowance under various Rules/Acts needs to be regulated strictly with a view to keeping its incidence to the barest minimum. The concept of Overtime should be utilised for achieving higher productivity and must not be invoked for completing the normal work of the day. Staff should not be booked on Overtime routinely and approval at an appropriately high level should be obtained before booking staff on overtime. Periodic review of incidence of overtime payment should be conducted at the level of Divisional Railway Manager, Heads of Department, Addl. General Manager or General Manager with a view to arresting the tendency towards increase in payment of Overtime Allowance

3. Subject to the above stipulations, it is hereby clarified that the Railway employees who are governed by the Statutory Acts like the Factories Act, Hours of Employment Regulations or those covered under rules for Departmental Overtime and who have opted for the revised scales of pay in terms of Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997, may be granted overtime allowance, on the basis of their emoluments in the revised scales of pay.

4. The emoluments, for the purpose of computation of rates of OTA will comprise the following :

a) **<u>Railway employees governed by Factories Act</u>**

i) Revised rates of pay
ii) DA
iii) CCA
iv) HRA
v) Cash equivalent of the advantage accruing through the concessional sale to workers of foodgrains and other articles as the workers, for the time being may be entitled to (excluding wages for Overtime work and Bonus).

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्र.सं.पी.सी.V / 42 आर.बी.ई.सं. 32/98

सं.पी.सी.V / 97/1/7/17 नई दिल्ली, दिनांक: 09-02-98

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/विशेष कार्याधिकारी
सभी भारतीय रेलें तथा
उत्पादन इकाइयां आदि
(डाकसूची के अनुसार)

विषय: वेतनमान एवं भत्तों के संशोधन के परिणामस्वरूप रेल कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता प्रदान करना.

.....

पांचवे केंद्रीय वेतन आयोग को केंद्र सरकार के कार्यालयों में समयोपरि भत्ते के भुगतान हेतु पर्याप्त औचित्य नहीं मिला है तथा इसे बंद करने की सिफारिश की है. इसके बदले में, उन्होंने सिफारिश की है कि साप्ताहिक अवकाश के दिनों में कार्य पर लगाए जाने वाले कर्मचारियों को प्रतिपूरक छुट्टियां प्रदान की जाएं.

2. इस मामले की रेलवे बोर्ड द्वारा सावधानी से जांच की गई है तथा यह विनिश्चय किया है कि विभिन्न नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत समयोपरि भत्ते के भुगतान को कड़ाई से विनियमित किया जाए ताकि इसे न्यूनतम रखा जा सके. समयोपरि की अवधारणा का इस्तेमाल अपेक्षाकृत अधिक उत्पादकता हासिल करने के लिए किया जाए तथा नेमी सामान्य कार्य को पूरा करने के लिए इसका सहारा न लिया जाए. कर्मचारियों को नेमी आधार पर समयोपरि पर बुक नहीं किया जाना चाहिए तथा समयोपरि पर कर्मचारियों को बुक करने से पूर्व उपयुक्त उच्च स्तर पर अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए. मंडल रेल प्रबंधक, विभागाध्यक्ष, अपर महाप्रबंधक अथवा महाप्रबंधक के स्तर पर समयोपरि के भुगतान की घटनाओं की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए जिससे कि समयोपरि भत्ते के भुगतान में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोका जा सके.

....2/-

S.No.PC-V/42

b) **Railway employees governed by IRMR**

All the items as shown in (a) above except Hours Rent Allowance.

c) **Railway employees governed by rules Under Department Overtime**

i Employees working in Loco Sheds and C&W Depot
Same as at (b) above

ii Other Railway employees governed under Departmental Orders

1) Revised rates of pay

5. The Allowances forming part of the computation of emoluments as clarified above, may be taken into consideration with effect from the dates and at the rates, notified from time to time.

6. The arrears, if any, on account of difference of OTA payable under these orders may be calculated after adjusting the OTA already paid to them. The arrears may be paid subject to availability of funds.

7. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

8. Hindi version is enclosed.

9. Please acknowledge receipt.

(R. Kashyap)
Executive Director, Pay Commission-I
Railway Board

Copy forwarded to :-

1. The G.M.(P), Railway Claims Tribunal, Railway Claims Tribunal, Central Railway Building, 3rd Floor, Vidyanidhi Marg, Ajmer
2. The G.M.(P), All India Railway Recruitment Cells, N.R. Railway Building, New Delhi and Secretary, Railway Recruitment Board, Chennai
3. The Director General, RDSO, Lucknow
4. The General Manager and FA & CAO, Metro Railway, Calcutta
5. The General Manager and FA & CAO, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur, Navi Mumbai
6. The General Manager and FA & CAO, CORE, Allahabad
7. The Principal, Railway Staff College, Vadodara
8. The CAO (Const.), MTP/KOP, Mumbai
9. The CAO (Const.), MTP/BSP, Varanasi
10. The Director, CAMTECH, Gwalior-474020
11. The Director, IRICEN, Pune, IRIEEN, Lodi Road, IPR, IRSME, Nasik Road, IRIEEN, Gorakhpur, Director, CTRE, Secunderabad
12. The Managing Director, RITES, RVNL, IRCON, IRCTC, CONCOR, all Railway Undertakings, Executive Director, CTRE
13. The Chairman and Managing Director, CORE, Secunderabad-500 017
14. Office of the Chief Project Administrator (Electrification), Indian Railway Construction Organisation for Electrification (IRCON), Gurgaon
Secretary, Railway Board
15. The Director, Railway Recruitment Board, Ajmer
16. The Joint Director (Finance), RDSO, Lucknow
17. The Joint Director, Rail Bhawan, Ministry of Railways
18. The Joint Director (Establishment), Railway Board, New Delhi
19. Chief Cashier, Western, Mumbai Railway, Churchgate, Mumbai-400 020
20. The Chairman, 2nd Pay Commission, Railway Board, New Delhi
21. The Chairman, 2nd Pay Commission

3. उपर्युक्त शर्तों के अध्यधीन, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि जो रेल कर्मचारी कारखाना अधिनियम, रोजगार के घंटे विनियम आदि जैसे सांविधिक अधिनियमों द्वारा शासित होते हों अथवा विभागीय समयोपरि के नियमों के अन्तर्गत आते हों तथा जिन्होंने रेल सेवा(संशोधित वेतन) नियम, 1997 के अनुसार संशोधित वेतनमानों में वेतन लेने के लिए विकल्प दिया हो, उन्हें संशोधित वेतनमान में उनकी परिलब्धियों के आधार पर समयोपरि भत्ता प्रदान किया जा सकता है.

4. समयोपरि भत्ते की दरों की गणना करने के प्रयोजन हेतु परिलब्धियों में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(क) कारखाना अधिनियम द्वारा शासित रेल कर्मचारी

(i) वेतन की संशोधित दरें
(ii) महंगाई भत्ता
(iii) नगर प्रतिपूरक भत्ता
(iv) मकान किराया भत्ता
(v) श्रमिकों को रियायती मूल्य पर प्रदान किए जाने वाले खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं, क्योंकि श्रमिक कुछ समय के लिए इसके पात्र हो सकते हैं, के जरिए प्राप्त होने वाले लाभ के बराबर नकद(जिसमें समयोपरि कार्य एवं बोनस के लिए मजूरी शामिल नहीं है.).

(ख) एच.ओ.ई.आर. द्वारा शासित रेल कर्मचारी

उपरोक्त(क) में उल्लिखित सभी मदें जिसमें मकान किराया भत्ता शामिल नहीं है.

(ग) विभाग के अन्तर्गत समयोपरि नियमों द्वारा शासित रेल कर्मचारी

(i) लोको शेड तथा कैरिज एंड वैगन डिपो में कार्यरत कर्मचारी
(ii) विभागीय आदेशों के अन्तर्गत शासित अन्य रेल कर्मचारी

(i) वेतन की संशोधित दरें.

ऊपर (२५) की तरह)

... 3/-

5. उपरोक्त स्पष्ट किए गए अनुसार, परिलब्धियों के परिकलन में शामिल भत्तों की गणना लागू होने की तारीख से तथा समय-समय पर अधिसूचित दरों पर की जाए.

6. इन आदेशों के अन्तर्गत देय समयोपरि भत्ते के अन्तर यदि कोई हो, के कारण बकायों की गणना, उन्हें पहले ही भुगतान किए जा चुके समयोपरि भत्ते को समायोजित करने के बाद की जाए. इन बकायों का भुगतान धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा.

7. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

8. कृपया पावती दें.

(आर. कश्यप)
कार्यपालक निदेशक, वेतन आयोग-I
रेलवे बोर्ड.